गलतियों की एक श्रृंखला

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- टी.पी. श्रीनिवासन
(महानिदेशक, केरल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तिरुवनंतपुरम)

6 फरवरी, 2019

"केरल बाढ़ राहत निधि की संघीय गिरावट को ठीक करने के लिए देखभाल की आवश्यकता है।"

पिछले वर्ष अगस्त महीनें में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राज्य के पुनर्निर्माण के लिए बाहरी सहायता से इनकार करने पर केरल और केंद्र सरकारों के बीच मतभेद फिर से गंभीर हो गये हैं, जिसे हम विधानसभा में केरल के राज्यपाल के भाषण में और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस पर केरल के एक मंत्री के बयान में देख सकते हैं। राज्यपाल न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम ने कहा था कि केरल सरकार ने केंद्र से बाढ़ प्रभावित राज्य के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनी उधार सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, ष्हम अभी भी इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुकूल प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री के.टी. जलील, जिन्होंने सम्मेलन में केरल का प्रतिनिधित्व किया, शिकायत की कि उन्हें इस मुद्दे पर बात करने की अनुमति नहीं दी गयी है। इसलिए बाढ़ के पैसे पर कड़वाहट अभी भी कायम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवर्तित विदेशी देशों के साथ बातचीत के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी संघवाद एक दोधारी तलवार साबित हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अब विदेशी सहायता की मांग को लेकर नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी माने जा रहे हैं। वे कई करोड़ की कमी को पाटने के लिए खुद को असहाय महसूसकर रहे हैं। केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराने में असमर्थ है, जबकि केरल को विदेशों से संसाधन मांगने से रोक दिया गया है, या तो केरल प्रवासी या दोस्ताना विदेशी सरकारों से।

वर्तमान स्थिति निर्णय की त्रुटियों और दोनों पक्षों पर गलतफहमी की एक श्रृंखला का परिणाम है। आपसी राजनीतिक संदेह और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की जटिलताओं की कमी के कारण टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री ने भले ही कूटनीतिक और सामरिक गलत बयानबाजी की हो।

कूटनीतिक स्थिति

2004 तक आपदा प्रबंधन के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के बारे में भारत के पास कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की आकांक्षा मजबूत प्रतिरोध के साथ मिली, तो नई दिल्ली ने महासभा में वोट देने के विचार पर जोर दिया। खेल योजना दो-तिहाई बहुमत को सुरक्षित करने और फिर सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करने में स्थायी सदस्यों को शर्मिंदा करने का प्रयास थी। दो झूठे अनुमान यह थे कि भारत आवश्यक संख्या में वोट हासिल करेगा और सुरक्षा परिषद महासभा के दबाव में लड़ेगी। वास्तव में, कई विधानसभा सदस्य मौजूदा स्थायी सदस्यों के लिए भी वीटो का

विरोध कर रहे थे और वीटो के साथ अधिक स्थायी सदस्य बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भारत ने सोचा था कि वह अन्य देशों पर जीत हासिल कर सकता है अगर उसे खुद के लिए इस तरह की सहायता मांगने के बजाय आपात स्थितियों में मदद करते देखा जाए।

2004 की सुनामी और हिंद महासागर में समुद्री डकैती के खतरे ने भारत को अपने नए रूख का परीक्षण करने का अवसर प्रदान किया। हर कोई आभारी था, लेकिन इससे भारत की स्थायी सदस्यता के दावे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे अन्य कारक भी थे जो भारत के दावे के खिलाफ थे। हालांकि, मोदी सरकार ने स्थिति में कुछ स्पष्टता लाने के लिए विदेशी सहायता से संबंधित नियमों को निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

2016 में तैयार किए गए नियमों ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी सहायता को दरकिनार नहीं करेगा, बल्कि व्यक्तियों, धर्मार्थ संस्थानों और फाउंडेशनों से भी नकद के रूप में राहत सहायता प्राप्त करेगा। यदि विदेशी सरकारों द्वारा नकद राशि द्विपक्षीय रूप से पेश की जानी थी, तो इस मामले के आधार पर माना जाएगा। क्षति की सीमा पूरी तरह से ज्ञात होने से पहले ही, मैंने अगस्त, 2018 की शुरुआत में केंद्र सरकार से नियम में एक उपयुक्त संशोधन करने का आग्रह किया था क्योंकि केरल में क्षति को संभालना मेरी क्षमता से परे था। लेकिन उस समय किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

यूएई की पेशकश

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा प्रस्ताव की गाथा अच्छी तरह से तब शुरू हुई जब यूएई अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री को सूचित किया गया कि राहत सहायता एक विशेष संकेत के रूप में दी जा रही है। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाकि यूएई 700 करोड़ रूपए प्रदान करेगा, उसी दिन केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रूपए के प्रावधान की घोषणा ने विवाद को जन्म दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यूएई नई दिल्ली की तुलना के लिए केरल में अधिक उदार था और केंद्र सरकार राजनीतिक विचारों के कारण केरल की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील नहीं थी। इसके अलावा, जानकारी का स्रोत यूएई में एक भारतीय व्यापारी होना चाहिए था।

तात्कालिक परिणाम द्विपक्षीय सहायता के किसी भी प्रस्ताव को बनाने के लिए अन्य सरकारों द्वारा अनिच्छा थी। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि क्या अन्य सरकारों का कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। जब दिल्ली में थाई राजदूत को एक भारतीय अधिकारी को राहत सामान सौंपने के समारोह में जाने से रोक दिया गया, तो दुनिया को यकीन हो गया कि भारत संसाधनों को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, केरल में भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ माकपा के बीच इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया।

यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ था कि केरल ने दान लेने के लिए विदेश में अपने मंत्रियों को भेजने के लिए एक नासमझ प्रस्ताव पेश किया। दान के आग्रह के अलावा, नकद दान के माध्यम से बहुत कम प्राप्त करने की स्पष्ट संभावना थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण की संभावना दूर हो गई क्योंकि केंद्र ने इन वैश्विक संगठनों से ऋण की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया जो राज्य सरकार ले सकती थी। सबरीमाला संकट के उद्भव ने राज्य सरकार की विश्वसनीयता को और अधिक नष्ट कर दिया और बाढ़ की क्षति पर अधिक सहानुभूति भी खो दी।

प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात को बनाए रखा था कि संविधान के अनुसार संसाधनों का संग्रह करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब केरल के सामने एकमात्र विकल्प कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक धन की मांग करना बच गया है। निस्संदेह, यह स्थिति त्रुटियों की एक त्रासदी है जो निर्णय लेने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता के साथ एक अपर्याप्त परिचितता के कारण होती है।

भारत एक संघीय राज्य है, लेकिन प्रकृति में एकात्मक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की बात सामने आ जाती है। अलग-अलग राज्यों को अपने पड़ोस में कुछ देशों से निपटने में कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन जब वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन की बात करते हैं, तो वे एक पतली रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकेंगे। अब प्रतिस्पर्धी संघवाद को फिर से काम करने के लिए विश्वास स्थापित होने में अधिक समय लगेगा।

GS World Committed To Excellence

केरल में बाढ़ का मुख्य कारण

- अन्य राज्यों की तरह केरल की बाढ़ का प्रमुख कारण बांधों से एक साथ पानी छोड़ना था। अत्यधिक वर्षा की लगातार चेतावनी के बाद भी बांधों से नियंत्रित जल छोड़ने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
- विश्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार 2015 का नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट स्पष्ट करता है कि मौसम की लगभग सटीक भविष्यवाणी के बावजूद बांधों के प्रबंधक-नौकरशाह समय पर नियंत्रित जल छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं।
- हमारे देश में अनुमानित वर्षा के आधार पर बांधों से जल छोड़ने की कोई नीति नहीं है, परन्तु विश्व के अधिकांश भागों में बांधों के प्रबंधन में मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार गतिशीलता दिखाई जाने लगी है।
- भाखड़ा बांध में इस प्रकार के प्रबंधन को अपना लिया गया है।
- हांलाकि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट अब वर्षा एवं मौसम से संबंधित सटीक पूर्वानुमानों पर तेजी से काम कर रहा है, परन्तु जब तक बांध प्रबंधक अधिकारियों को पूर्वानुमानों के अनुसार निर्णय लेने की छूट या दिशानिर्देश नहीं दिए जाते, तब तक समस्या का हल नहीं निकल सकता।
- भारत में आपातकालीन स्थितियों में एक बेसिन से दूसरे में पानी स्थानांतरित करने तथा जल भंडारण के लिए नहरों को जोड़ने आदि पर अभी काम किए जाने की आवश्यकता है।

जलमार्गों का अवरुद्ध होना

- केरल के तिरुअनंतपुरम में ही अकेले 23 छोटी धाराओं के पथ को अवरुद्ध कर दिया गया। यह भी बाढ़ का एक कारण रहा।
- इस तरह का अवरोध बाकायदा औपचारिक योजना के माध्यम से किया गया है। राज्य का अंतर्देशीय जलमार्ग विभाग केवल बड़े जलस्रोतों पर ही ध्यान देता है।
- जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नदियों के बेसिन पर आधारित बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।
- इस कार्यक्रम में बाढ़ की सबसे बुरी स्थिति के पूर्वानुमान पर काम किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में महानदी से आने वाली बाढ़ की समस्या को ब्रिटेन के सहयोग से सुलझाया जा रहा है।
- इसमें दूसरा चरण जल-भंडारण, जल-निकासी एवं आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का है।
- साथ ही कुछ मामलों में जागरुकता फैलाए जाने की जरूरत है। विमानतलों का विस्तार नदी के कछारों तक न किया जाए।

अधिक बारिश की वजह

- केरल में बारिश के दो मौसम होते हैं। पहले साउथवेस्ट मानसून बरसता है जो जून से सितंबर के बीच होता है। फिर आता है नॉर्थईस्ट मानसून।
- ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है।
- साउथवेस्ट मानसून में हवा समंदर से जमीन की ओर बहती है। इसीलिए इस मानसून में नमी ज्यादा होती है।
- फिर केरल में बड़े ऊँचे पहाड़ हैं-पश्चिमी घाट वाले।
- ये मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं इसीलिए केरल में खूब बारिश होती है।
- इस साल केरल में साउथवेस्ट मानसून बहुत मजबूत रहा है।

आवर्ती (बार-बार आने वाले) बाढ़ के कारण

- **भारी वर्षा:** यह भारत में बाढ़ का मुख्य कारण है। विशेष रूप से कम समय में अधिक बारिश बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे बाढ़ आने की आशंका ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए जुलाई, 2017 में माउंट आबू में 24 घंटों के अंतराल में बहुत भारी बारिश हुई।
- ऐसा लगभग 300 वर्षों में पहली बार हुआ है। हिल स्टेशन पर 24 घंटों में 700 मिमी वर्षा होती है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में बाढ़ का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन की घटना है।
- **नदियों में पानी के बहाव से लायी गयी मिट्टी या रेत:** नदियों की तलछटी में पानी के बहाव से जमा मिट्टी या रेत नदियों के जल वाहन की क्षमता को कम कर देती है, जिससे बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है।
- उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में 2 किमी से लेकर 14 किमी तक पानी के बहाव से लायी गयी मिट्टी या रेत का जमाव पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार बाढ़ का प्रमुख कारण है।
- **नालियों में रुकावट:** अवरुद्ध नालियां शहरी क्षेत्रों में विशेषकर महानगरों में बाढ़ का मुख्य कारण है।
- उदाहरण के लिए ड्रेनेज सिस्टम की विफलता दिसंबर, 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के प्राथमिक कारणों में से एक है, जिसके कारण लगभग 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी।
- **भूस्खलन:** उत्तर और उत्तर-पूर्व के पहाड़ी इलाकों में बाढ़ का प्रमुख कारण भूस्खलन है।
- उदाहरण के लिए जून, 2013 में भूस्खलन के कारण उत्तराखंड में नदियों के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होने के कारण बाढ़ की समस्या बनी रही जिसमें लगभग 5748 लोगों की मौत हो गयी।
- उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात और भूकंप तथा नदी के किनारों और जल निकायों के अतिक्रमण भी बार-बार आने वाले बाढ़ का मुख्य कारण हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. आवर्ती बाढ़ के आने के निम्नलिखित में से क्या कारण है?

   1. भारी वर्षा
   2. नालियो में रूकावट
   3. नदियों में पानी से लायी गयी मिट्टी
   4. भूस्खलन

   कूट:-

   (a) 1, 2 और 3
   (b) 2, 3 और 4
   (c) 1 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी।

1. **Which of the following are the reasons for recurring flood?**

   1. Heavy rainfall
   2. Blockage in drainage
   3. Soil carried by the water of river
   4. landslide

   Code:-

   (a) 1, 2 and 3
   (b) 2, 3 and 4
   (c) 1 and 3
   (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है? हाल ही विदेशी सहायता को लेकर केरल और केन्द्र के मध्य बढ़ते विवाद प्रतिस्पर्धी संघवाद को किस प्रकार प्रभावित किया है? चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. What is competitive federalism? How the increasing dispute between Kerala government and Centre regarding the foreign aid has influenced competitive federalism? Discuss.

(250 Words)

नोट : 5 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

GS World
Committed To Excellence